enquiry can be conducted and completed, it cannot be said as to what is the correct position.

(ii) Sheloving of certain proposed Steel Plants in South India

SHRI R KOLANTHAIVELU (Tiruchengode): Sir, the Salem Steel Plant's detailed project Report was prepared twice. The second DPR was accepted by the Government and the initial work was started. But now this DPR has been brushed aside. The Salem Steel Plant has just become a fabrication plant, getting plates from Rourkela Steel Plant and then processing it. While this is the fate of Salem Steel Plant along with this Vizianagaram Steel Plant was announced During last year's Chikmagalur election, Mangalore Steel Plant was announced After the crushing defeat of the ruling party, Mangalore Steel Plant has been put in cold storage. Viziangaram Plant has been shelved If the industrial climate is not good for the completion of these projects one can appreciate the Government's lukewarm attitude After the advent of the Janata Party at the Centre in 1977, Paradip Steel Plant idea was mooted. Within two years this project is already half-completed When the Government of India imports steel, naturally one gets incensed Now, steel is being imported But Salem Steel Plant has been sliced Vizianagaram Steel Plant and Mangalore Steel Plant has been shelved. I would like to know the reasons for this. I request that the Minister of Steel should make a detailed statement. He should clarify whether South India is not being neglected in this matter.

(iii) Loss of foodgrains for want of proper storage arrangements by the Food Corporation of India.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता।

भारतीय खाद्य निगम के कुप्रबन्ध के फलस्वरूप जहां आज हजारों कृषकों को अपना गेहूं समर्थन मूल्य से भी कम दामों पर बेचना पड़ रहा है वहां भण्डारण की दोषपूर्ण व्यवस्था से करोड़ो रुपयो का अनाज नष्ट होता जा रहा है। विगत दिनो विभिन्न समाचार-पत्रो में अनाज की बर्बादी के जो आंकड़े आये हैं, वे वास्तव में चौका देने वाले हैं। एक ही वर्ष में करोड़ो की हानि वास्तव में विचारणीय है। हम अपने उत्पादन का एक बड़ा भाग अव्यवस्था के फलस्वरूप नष्ट कर देते हैं। भारतीय खाद्य निगम की खरीदी, भण्डारण, रख-रखाव आदि के बारे में यद्यपि कई बार चर्चायें की जाती रही हैं किन्तु परिणाम शून्य है और आज स्थिति सुधार के बजाय खराबी की ओर है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हमारी इसी दोषपूर्ण नीति का ही परिणाम है कि हम रूस को निश्चित मात्रा मे समय पर गेहू नही दे सके है और न वियतनाम को दिए गए आश्वासन की ही पूर्ति कर सके है। आज यद्यपि खरीदी कही कही बढ रही है किन्तु उसकी स्थिति भी सन्तोषजनक नही है। खरीदा गया गहू बाहर खुले मैदानो में पड़ा है। उसे भरने के लिए गनीबैग्ज भी उपलब्ध नही है। यद्यपि निगम को इस बात का ज्ञान था कि उसे खरीदी करनी है और उस दृष्टि से कहां क्रय केंद्र होगे, कितनी खरीदी प्रत्येक केंद्र पर सम्भावित है, भण्डारण की क्या व्यवस्था होगी तथा यातायात का क्या प्रबन्ध है आदि, किन्तु ऐसा लगता है इन सभी बातों की ओर दुर्लक्ष किया गया है जिससे किसान भी परेशान है और गेहू बर्बाद होने की पूरी पूरी सम्भावनाये है। अत यह आवश्यक है कि इस ओर तुरन्त ध्यान दिया जाए और उचित व्यवस्था की जाए जिससे कि किसान परेशान न हो, अनाज बर्बाद होने से बचे व करोड़ो की आर्थिक हानि को रोका जा सके। इसी प्रकार वर्तमान मे भण्डारो मे रखे गए गेहू व चावल की पूरी हिफाजत की जाए अन्यथा अनाज खराब होकर अनुपयोगी होने की सम्भावना है जिससे कि आज हो रही करोड़ो की हानि और बढ़ सकती है। खाद्य निगम की कई दुर्व्यवस्थाओ की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सासदो को धरना भी देना पड़ता है। मैं माननीय कृषि मत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि सम्पूर्ण स्थिति को गम्भीरता से लें व तुरन्त प्रभावी कार्यवाही करे जिससे किसानो को समर्थन मूल्य मिले, अनाज बर्बादी से बचे व करोड़ो की आर्थिक हानि रोकी जा सके।

(iv) Demonstration by Nepalese in front of their Embassy in New Delhi

श्री मनी राम बागड़ी (मथुरा): उपाध्यक्ष महोदय, नैपाल के बारे में आप ने नियम 377 के अन्तर्गत मुझे अनुमति दी है, मैं सब से पहले महामानव डा० लोहिया को सलाम करूंगा जिन्होंने नैपाल दिवस मना कर के ....